



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I — खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 1974/श्रावण 31, 1896
No. 202] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 1974/SRAVANA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 22nd August 1974

No. 10(1)-Tar/74.—The Tariff Commission has submitted its Report (1974) on the Review of the progress of the Aluminium Industry as required in the Government's Resolution No. 11-Tar/71, dated the 10th December 1971. The Commission's recommendations and the Government's decisions thereon are given in the Table below :—

TABLE

Sl. No.	Recommendation of the Tariff Commission	Decision of the Government
(1)	(2)	(3)
1.	With regard to implementation of the Tariff Commission's recommendation made in its Report (1971) relating to adequate collection of data from the Small Scale sector and on objective evaluation thereof, the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi, informed the Commission that "there is no control either statutory or otherwise over the small units. As such, small units do not generally comply with the request made for the supply of any material. The Ministry of Industrial Development is consulting	Government have taken note of this recommendation for implementation as far as possible. The attention of the Small Scale Sector of the Aluminium Industry is also drawn to this recommendation for supplying the necessary data to the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.

(1)

(2)

(3)

the concerned authorities for a legislation for Small Scale Industries which may help in annual collection and quick tabulation of data relating to the entire small scale sector." The Commission considers that it is essential that complete data should be collected from the Small Scale Sector. The Commission hopes that the proposed legislation for collection of adequate data for small scale sector which would help objective evaluation of its performance would be speedily enacted.

A national Census of Small Scale Industries is currently in progress in all the States and Union Territories. The results of the Census are likely to be available by the end of 1974. A decision in regard to enacting the proposed legislation will be taken after Census results become available.

2. A power intensive industry like Aluminium Industry requires constant supply of power with minimum fluctuation of supply voltage. Apart from the production loss during the power-off periods, there would be additional mental losses during the re-start period. Cutting of power would cause physical damage to the smelter equipment and reduce the life of expensive pot linings. The power shortage is also likely to continue for some time to come. For these reasons it is considered desirable that the primary aluminium units which may propose to augment their power supply by installing their own generating sets should be permitted to do so, at least as a stand by.

The quantum of power required by the aluminium industry being substantial, setting up of generating sets by the units to serve as stand-by during 'power off' period is impractical. Consideration would however be given to the feasibility of setting up captive power stations for aluminium production.

3. The Aluminium Industry is at present in a fluid state. A detailed inquiry regarding the question of the continuance of protection to the industry would be undertaken in early 1976, by which time it is hoped that stable conditions would prevail and a more objective appraisal of the industry would be possible enabling specific recommendations being made to the Government.

Government have noted this recommendation.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

S. G. BOSE MULICK, Secy

कार्मिक मंत्रालय

संकल्प

डैरिफस

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1974

सं० 10(1)-डैर/74.—डैरिफ आयोग ने सरकार के संकल्प सं० 1(1)-डैर/71 दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 में यथापेक्षित एल्युमिनियम उद्योग की प्रगति ने पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में अपनी

रिपोर्ट (1974) प्रस्तुत कर दी है। आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के विनिश्चय नीचे सारणी में दिये गये हैं :—

सारणी

क्रमांक	टैरिफ आयोग की सिफारिश	सरकार का विनिश्चय
(1)	(2)	(3)
1.	<p>लघु क्षेत्र के आंकड़ों के यथेष्ट संचयन तथा उसके वस्तुपरक मूल्यांकन के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट (1971) में की गई उसकी सिफारिश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली ने आयोग को सूचित किया कि “लघु एककों पर कानूनी या अन्यथा कोई नियन्त्रण नहीं है। अतः लघु एकक सामान्यतः किसी माल की सप्लाई के लिए किये गये अनुरोध का अनुपालन नहीं करते। औद्योगिक विकास मंत्रालय संबन्धित अधिकारियों से लघु उद्योगों के सम्बन्ध में एक ऐसे विधान के लिए प्रारम्भ कर रहा है जो सम्पूर्ण लघु क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़ों के वार्षिक संचयन और उसके शीघ्र सारणीयन में सहायक हो सकें।” आयोग का विचार है कि यह आवश्यक है लघु उद्योग क्षेत्र के सम्पूर्ण आंकड़े संचित किये जाने चाहिए। आयोग आशा करता है कि लघु उद्योग क्षेत्र के यथेष्ट आंकड़े संचित करने के लिए प्रस्तावित विधान, जिससे उसके कार्य निष्पादन के वस्तुपरक मूल्यांकन में सहायता मिलेगी, शीघ्रतापूर्वक अधिनियमित किया जायेगा।</p>	<p>सरकार ने, यथासम्भव कार्यान्वित करने के लिए इस सिफारिश को नोट कर लिया है। विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली को आवश्यक आंकड़े सप्लाई करने के लिए एन्यूमिनियम उद्योग के लघु क्षेत्र का ध्यान भी इस सिफारिश की ओर दिलाया जाता है। लघु उद्योगों की देशव्यापी गणना इस समय सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। गणना के परिणाम 1974 के अंत तक उपलब्ध होने की आशा है। प्रस्तावित विधान को अधिनियमित करने के बारे में विनिश्चय, गणना के परिणाम उपलब्ध हो जाने के बाद लिया जायेगा।</p>
2.	<p>एन्यूमिनियम उद्योग जैसे पावर प्रधान उद्योग के सम्बन्ध में पावर की मतत् सप्लाई की आवश्यकता है जिसमें सप्लाई वोलटेज की घटबड़ कम से कम हो। पावर बन्द रहने की अवधियों के दौरान उत्पादन की हानि के अलावा घुट्टा चाल किये जाने की अवधि के</p>	<p>एन्यूमिनियम उद्योग के लिए आवश्यक पावर की मात्रा काफी होने की वजह से “पावर बन्द” रहने की अवधियों के दौरान संकट में सहारे के रूप में जेनेरेटर सेट स्थापित करना अव्यवहारिक है। तथापि, एन्यूमिनियम उत्पादन के लिए कंपटिब</p>

(1)

(2)

(3)

दौरान धातु सम्बन्धी अतिरिक्त हानियाँ भी होंगी। पावर की कटौती से समैलटर उपस्कर को वास्तविक क्षति पहुँचेगी और कीमती पोट लाईनिंग्स का जीवन कम होगा। ऐसी भी सम्भावना है कि आगामी कुछ समय तक पावर की कमी बनी रहेगी। इन कारणों से यह वांछनीय समझा जाता है कि जो प्राथमिक एल्यूमिनियम एकक स्वयं अपने जेनरेटिंग सेट स्थापित करके अपनी पावर सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव करें उन्हें कम से कम संकट में एक सहारे के रूप में ऐसा करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए।

पावर स्टेशन स्थापित करने की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

एल्यूमिनियम उद्योग इस समय अनिश्चितता की स्थिति में है। इस उद्योग के लिए संरक्षण जारी रखने के प्रश्न के बारे में विस्तृत जाँच 1976 के आरम्भ में की जाएगी, आशा है कि तब तक स्थिति में सहायित्व आ जायगा और इस उद्योग का अधिक वस्तु पर मूल्यांकन करना सम्भव हो सकेगा जिससे सरकार को विशिष्ट सिफारिशों की जा सकेंगी।

सरकार ने इस सिफारिश को नोट कर लिया है।

घादेश

घादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति सभी सम्बन्धों को प्रेषित की जाये।

एस० जी० बोस मल्लिक, सचिव।